



सरकार ने हर ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत में जन औषधि केन्द्रों की स्थापना की परिकल्पना की है: श्री अनंत कुमार देश भर में 1000 जन औषधि केन्द्रों की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये

Posted On: 18 JAN 2017 4:48PM by PIB Delhi

केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक और संसदीय कार्य मंत्री श्री अनंत कुमार ने आज यहां भारतीय फार्मा पीएसयू ब्यूरो (बीपीपीआई) और राष्ट्रीय युवा सहकारी सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) के बीच सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। इसका उद्देश्य मार्च 2017 तक 'मिशन 3000' केन्द्रों के एक हिस्से के तहत देश के शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही स्थलों पर 1000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों की स्थापना करना है। इस अवसर पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, शिपिंग, रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख एल.मंडाविया भी उपस्थित थे।

भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग की एक पहल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) एक विशेष मिशन है जिसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को किफायती मूल्यों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं मुहैया कराना है। पीएमबीजेपी योजना के लिए प्रमुख क्रियान्वयनकारी एजेंसी बीपीपीआई ही है।

पीएमबीजेपी की प्रगति का उल्लेख करते हुए श्री अनंत कुमार ने कहा कि पिछले दस वर्षों के दौरान जन औषधि केन्द्रों की संख्या सात गुना बढ़कर फिलहाल 750 के आंकड़े से भी ऊपर चली गई है। यही नहीं, देश भर में जन औषधि केन्द्रों की स्थापना के लिए लगभग 20,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और 5000 से भी ज्यादा आवेदनों को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश भर में हर ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत में जन औषधि केन्द्रों की स्थापना की परिकल्पना की है।

श्री कुमार ने 'स्वास्थ्य सुरक्षा' प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन का फिर से उल्लेख किया, जिसे देश के हर नागरिक को किफायती मूल्यों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं मुहैया कराकर साकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सरकार स्वदेशी जेनेरिक दवा उद्योग को बढ़ावा देने और इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में काम कर रही है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि पीएमबीजेपी इस दिशा में एक अहम कदम है जो आम आदमी के स्वास्थ्य संबंधी खर्च में खासी कमी सुनिश्चित करेगा और इसके साथ ही फार्मा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' मिशन को नई गति प्रदान करेगा।

श्री मंडाविया ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार पीएमबीजेपी के जरिये 'सभी के लिए किफायती दवाओं' के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही है, जिसके तहत वर्तमान में 750 से भी ज्यादा स्टोर हैं और इनके पोर्टफोलियो में 600 दवाएं और 154 शल्य एवं उपभोक्ता वस्तुएं हैं। उन्होंने कहा कि एनवाईसीएस के साथ हाथ मिलाकर देश के युवाओं की ऊर्जा का उपयोग इस लक्ष्य की प्राप्ति में किया जाएगा।

सरकारी अस्पतालों में स्थापित किये जाने वाले इन केन्द्रों को वित्तीय सहायता के रूप में 2.5 लाख रुपये तक की सक्रिय वित्तीय मदद सरकार द्वारा दी जा रही है। इसी तरह संबंधित व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। उधर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों तथा दिव्यांगजनों के लिए विशेष एवं उदार शर्तें तय की गई हैं।

इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में फार्मास्यूटिकल्स विभाग में सचिव श्री जय प्रिय प्रकाश, बीपीपीआई के सीईओ श्री विप्लव चटर्जी, एनवाईसीएस के अध्यक्ष श्री राजेश पांडे और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी शामिल थे।

वीके/आरआरएस/एम- 183

(Release ID: 1480682) Visitor Counter : 11

